एफ.पी.ओ. मेला "तरंग-सामूहिकता का उत्सव" में

माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चन्द कटारिया के संबोधन का प्रारूप

दिनांक 03 मार्च 2024, रविवार	**समय : 5.00 PM**	**स्थान : श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र**

- भारतीय उद्यमिता संस्थान के निदेशक
  डॉ. ललित शर्मा जी,
- भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री ध्रुव चरण बाल जी,
- नाबार्ड के श्रेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक
  श्री नबीन कुमार रॉय जी,
- एनजीओ अमरी मिल्लेट्स के प्रतिनिधि
  - श्री दीपज्योति कंवर जी
  - श्री केनेडी फांग्चो जी,
- मेले में भाग ले रहे उद्यमियों एवं
- किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधिगण
- देवियों और सज्जनों,

नमस्कार !

मुझे राष्ट्रीय स्तर के **"एफपीओ मेला तरंग- सामूहिकता का उत्सव"** में आप सभी को संबोधित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मुझे खुशी है कि यह मेला प्रतिभागियों को शहरी उपभोक्ताओं से परिचित कराने, बाजार की मांग का आकलन करने, अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए उपभोक्ता प्राथमिकताओं का आकलन करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।

यह देखकर खुशी हो रही है कि देश भर के प्रमुख किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) ने इस मेले में भाग लिया है और अपने उत्कृष्ट उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की है। इस मेले ने लोगों को प्राकृतिक उत्पादों का स्वाद चखने और अनुभव करने का अवसर प्रदान किया है। मैं कृषि और किसानों के समर्थन तथा इस मेले के आयोजन के लिए नाबार्ड को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मैं समझता हूं हमारे राष्ट्र की समृद्धि तथा समावेशी विकास में कृषि एक प्रमुख क्षेत्र तथा सफलता की कुंजी है। यह हमारे देश के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए कृषि को तत्काल और केंद्रित तरीके से विकसित करने की जरूरत है।

कृषि विकास के साथ-साथ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य तक पहुंचने और हमारे देश की कृषि पर निर्भर बड़ी आबादी के कल्याण एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत गंभीरता से काम कर रही हैं।

यह अनुमान लगाया गया है कि कृषि में वृद्धि गरीबों की आय बढ़ाने में औसतन दो या तीन गुना अधिक कारगर है। देश के एकीकृत विकास को देखते हुए कृषि को भी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और भौतिक बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित विकास ग्रामीण-शहरी अंतर को कम करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

ग्रामीण समृद्धि का मूल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास पर निर्भर है। इस संदर्भ में कृषि-प्रसंस्करण उद्योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालाँकि, विकास को बढ़ावा देने तथा गरीबी और बेरोजगारी दूर करने का साधन बनाने के लिए कृषि क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता है।

मैं हमारी विकास रणनीति के संदर्भ में कृषि की रूपरेखा को उजागर करने के लिए कुछ तथ्यों और आंकड़ों को याद दिलाना चाहूंगा। भारत के पास वैश्विक भूमि का लगभग 3 प्रतिशत और विश्व के 5 प्रतिशत से कम जल संसाधन हैं, लेकिन यह वैश्विक आबादी का लगभग 20 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से अधिक पशुधन का भरण-पोषण करता है।

संसाधनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विश्व औसत की तुलना में लगभग 4 से 6 गुना कम है। फिर भी, हम दुनिया की सबसे बड़ी कृषि अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं और चावल, गेहूँ, चीनी, कपास, मसाले, फल और सब्जियों के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं।

6 लाख से अधिक गांवों में लगभग 14 लाख 50 हजार ग्रामीण परिवार हैं। छोटे और सीमांत किसान कुल भूमि मालिकों का लगभग 82 प्रतिशत हैं। अमेरिकी कृषि में 500 हेक्टेयर की तुलना में भारत की औसत जोत लगभग 1.5 हेक्टेयर है, जो अब तक हमारे राष्ट्रीय कार्यबल का सबसे बड़ा नियोक्ता है और लगभग 60 प्रतिशत लोगों को आजीविका प्रदान करता।

एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 75 वर्षों में भारत ने कृषि के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। भारत का खाद्य उत्पादन तीन गुना हो गया। देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाली हरित क्रांति अपना काम कर चुकी है। अब हमें एक और हरित क्रांति की आवश्यकता है, जो उत्पादकता को और अधिक बढ़ाए और ग्रामीण आबादी के लिए आय और रोजगार के अवसर पैदा करे।

हालाँकि हमारा खाद्य उत्पादन बढ़ा है, फिर भी हमें अपने उत्पादकता स्तर को बढ़ाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें उत्पादकता के इस अंतर को पाटने की जरूरत है।

हमारी वैज्ञानिक सफलताएँ, बेहतर तकनीकें और नवप्रवर्तन विकास को गति प्रदान करने वाले माध्यम हैं। हालाँकि, हमें वैज्ञानिक नवाचारों को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने की आवश्यकता है।

अक्सर देखा गया है कि प्रयोगशाला में सफलताएँ वास्तविक कार्य क्षेत्र पर गायब होती हैं, क्योंकि प्रयोगशाला से कार्य क्षेत्र तक प्रौद्योगिकी के प्रसार की गति धीमी होती है। इस विषय पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत दुनिया में खाद्य अनाजों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यहां फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण, उत्पाद विकास और मूल्य-संवर्धन का स्तर बहुत कम है, जिससे विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं नुकसान होता है। मैं समझता हूं इसमें उद्योग जगत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उद्योग जगत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को निवेश के विकल्प के रूप में देख सकता है।

मैं सभी संबंधित लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे इन मुद्दों पर विचार करें और सामूहिक रूप से कृषि और इसके संबद्ध क्षेत्रों को "विकसित भारत" के लक्ष्य को साकार करने के लिए शक्तिशाली माध्यम बनाने पर जोर दें।

कृषि अपने सहयोगी क्षेत्रों के साथ विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कृषि क्षेत्र में विकास के लिए किसानों और वैज्ञानिकों को मिलकर काम करना होगा।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार कृषि क्षेत्रों के विकास और हमारे किसान मित्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए समर्पित रूप से काम कर रही है।

हमारे किसान मित्रों के आर्थिक विकास के साथ-साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), परंपरागत कृषि विकास योजना जैसे कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

मैं हमारे उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए नाबार्ड को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन को मजबूत करने में सहायक होगा। यह आयोजन हमारी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए आत्मनिर्भर बनने के हमारे प्रयास का एक प्रमाण है।

आशा है कि यह मेला हमारे प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" में योगदान देने के लिए हमारे उद्यमियों के लिए एक सफल आयोजन साबित होगा।

पुनः इस मेले की सफलता के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

धन्यवाद।

जय हिन्द।